भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1211

03 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: डिजिटल कृषि मिशन के उद्देश्य

1211. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

श्री मलैयारासन डी.:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मिशन के उद्देश्य क्या हैं और इस मिशन के अंतर्गत किन-किन प्रौद्योगिकीय उपकरणों को बढ़ावा दिया जा रहा है;

(ग) इस मिशन हेतु कुल कितनी निधि आवंटित की गई है और किन-किन क्षेत्रों में डिजिटल रूपांतरण करने का लक्ष्य हैं;

(घ) इस मिशन के अंतर्गत कितने किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ङ) विशेषकर तमिलनाडु के अरानी और कल्लाकुरिची निर्वाचन क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए डिजिटल अवसंरचना और कनेक्टिविटी को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ङ.): सरकार ने 2 सितंबर, 2024 को 2817 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य देश में एक मजबूत डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करना है, ताकि किसान-केंद्रित डिजिटल समाधानों को आगे बढ़ाया जा सके और देश के सभी किसानों को समय पर और विश्वसनीय फसल संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। इस मिशन में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफ़ाइल मैप तथा केंद्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली अन्य आईटी पहलों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। एग्रीस्टैक परियोजना इस मिशन के प्रमुख घटकों में से एक है जिसमें कृषि क्षेत्र में तीन मूलभूत रजिस्ट्री या डेटाबेस शामिल हैं, यानी किसानों की रजिस्ट्री, भू-संदर्भित गाँव के नक्शे और फसल बोई गई रजिस्ट्री, जो सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाई और रखी जाती हैं। सरकार इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु सहित सभी राज्यों को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है और तमिलनाडु अपने किसानों को योजना सहायता प्रदान करने के लिए एग्रीस्टैक डेटा का उपयोग कर रहा है।

******